बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 172 ● नई दिल्ली ● वीरवार 23 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

नरेला इलाके में जूते की फैक्टरी में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं; दमकलकर्मी मौके पर

नई दिल्ली । नरेला औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार सुबह एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग ए ब्लॉक में स्थित एक जूता बनाने वाली फैक्टरी में लगी है। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने पूरी फैक्टरी को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत सूचित किया गया। सूचना के तुरंत बाद दिल्ली दमकल की 17 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग किस वजह से लगी है अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी की हत्या- फोन चार्जर की तार से गला घोंटा, दुष्कर्म की आशंका; पुराने नौकर पर शक

नई दिल्ली । दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित कैलाश हिल इलाके में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घरेलू सहायक पर मुख्य रूप से संदेह जताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। मृतका के माता-पिता सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के बीच जिम के लिए घर से निकले थे। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान घर में वारदात को अंजाम दिया गया। जब दंपति वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को घर में मृत अवस्था में पाया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

हत्या से पहले की गई मारपीट

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में मृतका के सिर और गर्दन पर चोट के निशान पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या गला घोंटकर की गई है और इसमें मोबाइल चार्जर के वायर का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने

आ रही है।

इकलौती बेटी थी मृतका, कर रही थी यूपीएससी की तैयारी

इसके अलावा दुष्कर्म के बाद हत्या की भी आशंका जताई जा रही है, हालांकि इस संबंध में पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। मृतका ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और इन दिनों संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तैयारी कर रही थी। वह इकलौती बेटी थी। उसकी इस तरह की मौत से परिवार गहरे सदमे में है।

एजेंसी से नौकर रखा था, पुलिस से कराया था सत्यापन

जांच के दौरान सामने आया है कि संदिग्ध घरेलू सहायक है, जिसकी पहचान राहुल मीणा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। अधिकारी ने एजेंसी से नौकर राहुल मीणा को रखा था। आरोपी का पुलिस से सत्यापन कराया गया था। बताया जा रहा है कि उसे करीब डेढ़ महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। परिवार को उस पर घर के सामान से जुड़े पैसों में हेराफेरी का शक था, जिसके बाद उसे हटाया गया था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने इसी रंजिश के चलते बदला लेने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपी को घटना के समय के आसपास इलाके में देखा गया है, जिससे शक और गहरा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी सचाई सामने लाई जा सके।

पीतमपुरा में सीएम रेखा गुप्ता ने किया वॉटर एटीएम का उद्घाटन, कार्ड से मिलेगा 20 लीटर पानी रोजाना

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयू ब्लॉक, पीतमपुरा में वॉटर एटीएम का उद्घाटन किया। साथ ही नागरिकों को वॉटर एटीएम कार्ड भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने इस सुविधा का शुभारंभ करते हुए जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा, एक साल में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से रोजाना दिल्ली की जनता को किसी न किसी रूप में नया उपहार रोजाना मिल रहा है। कभी नीति , कभी काम, कभी निर्माण और कभी प्रशासनिक सुधार के रूप में और आज एक नए ओर की कदम बढ़ाते हुए जहां पूरा देश इस समय भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है और पानी की कमी के कारण लोग परेशान थे, हमने दिल्ली में ये नया वॉटर एटीएम का उद्घाटन किया है। जो एक बड़ा आरओ प्लांट है, जिसकी क्षमता हर घंटे में 2000 लीटर पानी देने की क्षमता रखती है। सीएम ने कहा, इस तरह का वॉटर एटीएम कार्ड हम हर झुग्गी परिवार को दे रहे हैं। इससे वो 20 लीटर पानी रोजाना अपने घर लेकर जा सकते हैं जो कि शुद्ध पानी है।

ये आरओ प्लांट लोगों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला है, बिना किसी पैसे के ये पानी लोगों को मिलने वाला है इस काम को हम और आगे बढ़ाते हुए हर एक ऐसा क्षेत्र जहां पानी की दिक्कत है उन सब तक पानी मिले इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी।

केजरीवाल ने ममता बनर्जी से फोन पर की बात, समर्थन जताकर बोले- लोकतंत्र की अहम लड़ाई लड़ रहीं दीदी

नई दिल्ली ।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी देश के लोकतंत्र की सबसे कठिन और अहम लड़ाइयों में से एक लड़ रही हैं।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी से फोन पर बात की और उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, अभी ममता दीदी से फोन पर बात हुई। उन्हें पूरा समर्थन और एकजुटता जताई। वह बेहद कठिन लड़ाई लड़ रही हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी जी सभी संस्थाओं, यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके बावजूद वह हारेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले चुनाव आयोग ने भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रस्तावित रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में रैली की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को कुछ घंटों में मंजूरी मिल जाती है, लेकिन उनकी रैली को रोका गया। उन्होंने कहा कि मैं वहां फिर भी जाऊंगी, बैठूंगी और चाय पियूंगी। ममता का यह बयान भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कॉलिन स्ट्रीट इलाके में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आया। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को 152 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 मई को होगी। राज्य में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, जहां सत्तारूढ़ टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है, जबकि भाजपा सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है।

दिल्ली में पसरता कंक्रीट का जंगल, 10 साल में 7 डिग्री बढ़ा पारा; अर्बन हीट आयलैंड से हालात

नई दिल्ली । दिल्ली के तापमान में पहले की तुलना में तेजी से बदलाव हुआ है। पिछले 10 साल में करीब 7 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसका खामियाजा राजधानी ही नहीं देश के हर कोने में सबको भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली गर्म द्वीपों का शहर बनती जा रही है। 2014 की मई में दिल्ली में अमूमन 30-33 डिग्री तक रहने वाला पारा मई 2024 में 40 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि यह दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। इसकी पुष्टि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की कई रिपोर्ट करती हैं। इसे जलवायु परिवर्तन का असर कहें या ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप... लेकिन देश की राजधानी साल दर साल हीट आइलैंड बन रही है। अनुमान है कि इस साल 24 अप्रैल तक लोग 43 डिग्री से ऊपर का तापमान झेलेंगे। बारिश के पैटर्न में बदलाव, खासकर मानसून से पहले के समय में बेमौसम बारिश के कारण तापमान बदला है। जब किसी शहर में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में तापमान में अधिक बढ़ोतरी हो जाती है, उसे अर्बन हीट आइलैंड कहते है। इसकी बड़ी वजह है इंसानी गतिविधियां। किसी भी शहर को हीट आइलैंड बनने में सबसे अहम रोल होता है उसकी बसावट का। वो शहर किस तरह का है, वहां इमारतें कैसी हैं और उसे किस तरह से डिजाइन किया गया है। यही बातें सबसे अहम होती हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान बढ़ने और इनके हीट आइलैंड में तब्दील होने में भी यही फैक्टर जिम्मेदार हैं। पिछले चार दशकों में दिल्ली में कंक्रीट का जंगल काफी हद तक बढ़ा है, जो अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव में भी वृद्धि कर रहा है। 2000 के बाद दिल्ली में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। निर्माण कार्यों में इजाफा हुआ। खाली पड़ी जमीन पर फ्लैटों का निर्माण हुआ है, तो हरित क्षेत्र बढ़ाने के नाम पर भी वृक्ष के बजाय झाड़ियां अधिक लगाई गईं। 2003 में दिल्ली का 31.4 प्रतिशत हिस्से पर निर्माण था, जबकि अब यह बढ़कर 40 प्रतिशत को पार कर चुका है। बड़े पैमाने की मौसमीय स्थितियों लगातार उच्च दाब, साफ आसमान और शुरुआती लू की स्थितियों के कारण हो सकता है, जो जलवायु परिवर्तन और जेट स्ट्रीम में बदलाव से जुड़े हैं, जिससे क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा लंबे समय तक बनी रहती है।

-संजय कुमार मिश्रा, पर्यावरण विशेषज्ञ

विकसित भारत की परिकल्पना शहरी विकास के बिना संभव नहीं है। शहरों को विकास का इंजन माना जाता है, किंतु तीव्र होते जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के कारण हमारे शहर आज इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

आजादपुर मंडी के एंट्री गेट पर लगेगी हाईटेक मशीन, चलते ट्रक का कर देगी वजन, मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली । आजादपुर मंडी में अब चलते ट्रकों का वजन हो जाएगा। इसके लिए कृषि उपज विपणन समिति ने स्मार्ट वेट इन मोशन सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस तकनीक से मंडी में हेराफेरी रोकने, राजस्व बढ़ाने, ट्रकों की लंबी लाइन खत्म करने और ब्लैकलिस्ट वाहनों पर नजर रख सकते हैं। इसे मंडी के सबसे व्यस्त प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा, जहां से फल और सब्जियों से लदे ट्रक मंडी में घुसते हैं। आजादपुर मंडी में इससे वाहनों की एंट्री व्यवस्था बदल जाएगी। मंडी प्रशासन ने करीब 28.83 लाख रुपये खर्च कर मुख्य एंट्री गेट पर स्लो स्पीड वेट इन मोशन सिस्टम लगाने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। यह ऐसी मशीन होगी, जिसमें ट्रक को पूरी तरह रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन धीमी रफ्तार से प्लेटफॉर्म से गुजरेंगे और उनका वजन अपने आप दर्ज हो जाएगा। इस सिस्टम में सिर्फ वजन नहीं, बल्कि निगरानी की भी व्यवस्था होगी। इसमें आरएफआईडी डाटा, कैमरा इंटीग्रेशन, अलर्ट सिस्टम और रिकॉर्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं रहेंगी। ब्लैकलिस्ट या संदिग्ध वाहनों की पहचान होने पर अलर्ट भी दिया जा सकेगा। अभी मंडी में कई जगह वजन पारंपरिक कांटों या मैनुअल व्यवस्था से होता है। इसमें समय ज्यादा लगता है जिससे ट्रकों की कतार लग जाती है। मंडी से जुड़े लोगों का कहना है कि सुबह और देर रात माल आने के समय कई बार लंबा जाम लग जाता है। मुख्य एंट्री गेट पर रोजाना भारी दबाव रहता है, क्योंकि बड़ी संख्या में फल-सब्जी से लदे ट्रक इसी रास्ते से प्रवेश करते हैं।

एहसान नहीं,

इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण। यह विधेयक 2023 में पारित हो चुका है और पिछले सप्ताह सरकार ने इसे लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें संशोधन के लिए नया बिल लाया गया था लेकिन वह पारित नहीं हो पाया। मेरा मानना है कि आरक्षण कोई एहसान नहीं है बल्कि महिलाओं का हक है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा सरकार कह रही है कि लोकसभा के लिए यह कानून 2029 में लागू हो जाएगा। अब चूंकि विपक्ष ने इसे परिसीमन से जोड़ कर देखा इसलिए हमलावर होना लाजमी था। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा सीटों की संख्या 850 होने के बाद इसे लागू करने के बजाय मौजूदा संख्या पर ही लागू किया जाए। परिसीमन को लेकर विपक्ष की कई आशंकाएं हैं। मैं उन आशंकाओं को लेकर यहां बात नहीं करूंगा। मैं महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की बात करूंगा। आरक्षण जितनी जल्दी लागू हो, उतना ही बेहतर होगा क्योंकि बहुत सारा वक्त हम खो चुके हैं। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में हम पीछे रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की वैश्विक भागीदारी करीब 20 प्रतिशत रही है जबकि हमारा अधिकतम आंकड़ा भी कभी 14 प्रतिशत के पार नहीं जा पाया है। आधी आबादी को राजनीति में केवल एक तिहाई हिस्सा मिलने में आखिर इतना वक्त क्यों लग गया इस पर चर्चा से पहले चलिए जरा लोकसभा के प्रथम चुनाव को याद कर लेते हैं। पहला चुनाव 1951-1952 में हुआ। उसके लिए मतदाताओं का जो सर्वेक्षण हुआ उसमें 28 लाख महिलाओं ने अपना नाम लिखवाने के बजाय यह लिखवाया कि वो अमुक व्यक्ति की बीवी है या फिर अमुक व्यक्ति की मां है या बहन हैं। उस जमाने में देश के कई हिस्सों में यही प्रचलन था। महिलाओं को उनके नाम से नहीं बल्कि रिश्तों से पहचान मिलती थी। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन इतने खफा हुए कि उन्होंने ऐसे 28 लाख नामों को सूची से बाहर करने का फैसला किया। वो क्रांतिकारी कदम था। समाज को लगा कि महिलाओं का हक मारा गया है और अगले चुनाव में ऐसी महिलाओं ने आगे बढ़ कर नाम दर्ज कराए। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको यह अंदाजा हो सके कि भारतीय महिलाओं ने राजनीतिक व्यवस्था की पगडंडी से शुरुआत करते हुए पक्की सड़क और आज हाइवे तक का सफर पूरा किया है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा के उस पहले चुनाव में भी 489 सदस्यों में 22 महिलाएं जीत कर आई थीं जो कुल संख्या का केवल 4.4 प्रतिशत थीं। उसके बाद के आंकड़े देखिए- महिलाओं की संख्या दूसरी लोकसभा में 5.4 प्रतिशत, तीसरी में 6.7 प्रतिशत, चौथी में 5.9 प्रतिशत, पांचवीं में 4.2 प्रतिशत, छठी में 3.4 प्रतिशत, सातवीं में 5.1 प्रतिशत, आठवीं में 8.11 प्रतिशत, नौवीं में 5.3 प्रतिशत, दसवीं में 7 प्रतिशत, ग्यारहवीं में 7.4 प्रतिशत, बारहवीं में 8 प्रतिशत, तेरहवीं लोकसभा में 8.8 प्रतिशत तथा चौदहवीं लोकसभा में 8.1 प्रतिशत ही थी। पहली बार पंद्रहवीं लोकसभा में 10.9 प्रतिशत महिलाएं चुनकर आईं। उसके बाद आंकड़े बढ़े। सोलहवीं लोकसभा में आंकड़ा 11 प्रतिशत तक पहुंचा। सत्रहवीं और अठारहवीं लोकसभा का आंकड़ा 14 प्रतिशत के आसपास रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की भागीदारी की रफ्तार अत्यंत धीमी रही है। वैसे भागीदारी बढ़ाने की कोशिश बहुत लोगों ने की। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उनकी बनाई एक कमेटी ने शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया था। इसी सुझाव के मद्देनजर पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया। उसके बाद विधानसभा और लोकसभा के लिए भी ऐसी मांग उठी। सितंबर 1996 में पहली बार एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया लेकिन बात बनी नहीं। उस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। दरअसल एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में ही नहीं था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी महिला आरक्षण बिल पास कराने की कोशिश हुई। उस वक्त आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी के हाथ से बिल की प्रति छीन कर फाड़ दी थी। मैं उस समय सदन में था और अटल जी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि लालू जी ने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया लेकिन यहां महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने हर वक्त महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। जून 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पास करा लिया लेकिन आरजेडी और सपा के भीषण विरोध के कारण लोकसभा में पास नहीं हो सका। मगर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सोच को अमली जामा पहनाने वाले अमित शाह की खासियत है कि तय कर लिया तो उसे अंजाम तक हर हाल में पहुंचाएंगे। 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया। मांग उठी थी कि वर्ष 2024 में ही आरक्षण लागू कर दिया जाए लेकिन शायद वो संभव नहीं था। सरकार इसे 2029 में लागू करने पर अडिग थी लेकिन अब अड़ंगा लग गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी महिलाएं राजनीति की धारा को पवित्रता की राह पर आगे ले जाएंगी। हमारी बेटियों ने धरती से लेकर नील गगन तक को अपनी प्रतिभा से आलोकित किया है। राजनीति भी उनकी प्रतिभा से आलोकित हो, यही कामना है मगर अड़चनें बहुत हैं। आगे-आगे देखिए होता है क्या बस एक बात समझ में नहीं आती कि जब सभी दल महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात करते हैं तो फिर यह लागू क्यों नहीं हो रहा है सभी राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब उनसे पूछो कि महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट क्यों नहीं देते तो जवाब होता है कि वे जीत नहीं पातीं। दरअसल पुरुषवादी मानसिकता से हमारी राजनीति भी बाहर नहीं आ पा रही है।

भारत-बांग्लादेश : भर रही दरार

भारत और बांग्लादेश संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से गहरे रहे हैं जो 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका से बने हैं। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी जो द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बने। नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते किसी कूटनीति से कहीं आगे जाते हैं। साझा सीमाएं, साझा नदियां और सांस्कृतिक नजदीकी इन रिश्तों को खास बनाती हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत और बांग्लादेश में हिन्दुओं की हत्याओं के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई दरार अब धीरे-धीरे भरने लगी है। संबंधों में तल्खी के बावजूद भारत ने हमेशा दुःख-सुख में बांग्लादेश का साथ दिया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़े असर ने दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला दिया।

ऐसे वक्त में भारत ने 'पड़ोसी प्रथम' नीति को जमीन पर उतारते हुए बांग्लादेश का साथ दिया। बांग्लादेश ने भारत से डीजल सप्लाई बढ़ाने की गुजारिश की थी तब मोदी सरकार ने दोनों देशों के बीच मौजूदा पाइपलाइन के जरिए डीजल की सप्लाई जारी रखी और सप्लाई बढ़ाने का भरोसा भी दिया। यद्यपि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, स्वर्गीय प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं जिनके शासनकाल में दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट का दौरा देखा गया था लेकिन तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी नई सरकार भारत के साथ द्विपक्षी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। भारत ने भी बार-बार साबित किया है कि वह बांग्लादेश का भरोसेमंद साझेदार है। अब खबर यह है कि मोदी सरकार ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति कई मायनों में रणनीतिक मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि पड़ोस के देश में उच्चायुक्त की नियुक्ति पाने वाले त्रिवेदी पहले राजनीतिक व्यक्ति होंगे। इससे पहले पड़ोसी देशों में वह पद भारतीय विदेशसेवा के अधिकारियों को ही दिया जाता रहा है। इस नियुक्ति में कूटनीतिक हल्कों में एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि क्या कूटनीति केवल विदेश सेवा के अधिकारियों तक सीमित है या फिर कोई नॉन डिप्लोमैट भी किसी देश का उच्चायुक्त बन सकता है। भारतीय संविधान और विदेश मंत्रालय के नियम सरकार को यह अधिकार देते हैं कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मिशन प्रमुख नियुक्त कर सके जो देशके हितों की रक्षा करने में सक्षम हो। इनका चयन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ही किया जाता है। ऐसी नियुक्तियों के उदाहरण हमें पहले भी मिलते रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रसिद्ध हिन्दी कवि और शिक्षाविद डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में प्रेस और सांस्कृतिक अटैची के रूप में नियुक्त किया था। डाक्टर सुमन 1956 से 1961 तक काठमांडू में रहे और उन्होंने भारत-नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों और साझा विरासत को आगे बढ़ाया।

पत्रकार कुलदीप नायर 1990 के दशक में यूके में भारत के उच्चायुक्त रहे, जो एक गैर-सरकारी और गैर-राजनयिक पृष्ठभूमि से थे। इसी तरह, प्रख्यात विधिवेत्ता और राजनेता डॉ. एल.एम. सिंघवी को भी यूके में उच्चायुक्त के रूप में कूटनीतिक कमान सौंपी गई थी। हाल के वर्षों में देखें तो पूर्व आईपीएस अधिकारी अहमद जावेद को सऊदी अरब में भारत का राजदूत बनाया गया था। यहां तक कि न्यूजीलैंड जैसे देशों में पूर्व सैन्य अधिकारियों (एडमिरल) को भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। दिनेश त्रिवेदी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और बांग्लादेश के मामलों की अच्छी समझ रखते हैं। वे बांग्लादेश के साथ सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ, व्यापार और सांस्कृतिक मुद्दों की बारीकियां जानते हैं। रेल मंत्री रहते हुए वे बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट संभाल चुके हैं। उनका अनुभव देशके काम आ सकता है। मोदी सरकार ने उनकी नियुक्ति के जरिए दोनों देशों के संबंधों को दोबारा पटरी पर लाने का संकेत दे दिया है। प्रायः देखा गया है कि विदेश सेवा के अधिकारी सरकारी प्रोटोकाल के तहत काम करते हैं और वह नियमों के तहत बंधे होते हैं। जबकि राजनीतिक व्यक्ति किसी दायरे में नहीं बंधते और वह खुलकर काम करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के विदेशमंत्री खलीलुर रहमान भारत आए थे और उन्होंने गंगाजल संधि पर फिर से बातचीत शुरू की थी और यह भी संकेत दिया था कि बांग्लादेश की विदेशनीति किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। चीन के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया था यह जीरो-सम गेम नहीं है और भारत बाहरी पार्टनर नहीं बल्कि अच्छा साझीदार है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त बनने के बाद दिनेश त्रिवेदी, दोनों मुल्कों में ट्रेड और रेल, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम योगदान दे सकते हैं। वे बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर कर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति सामान्य कूटनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्गठन भी हो सकता है। जानकारों का मानना है कि ऐसा करके मोदी सरकार यह दर्शा रही है कि वह पड़ोस में सक्रिय, अनुभवी और राजनीतिक रूप से मजबूत प्रतिनिधि भेजकर संबंधों को नई दिशा देना चाहती है। हालांकि, उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इस पहल पर बांग्लादेश किस तरह सकारात्मक जवाब देता है। उम्मीद है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन और भारत के बीच संबंधों में संतुलन बनाकर चलेंगे। भारत बांग्लादेश के विकास में पहले की ही तरह भूमिका निभाने को तैयार है।

सम्पादकीय...

महिला आरक्षण विधेयक - विपक्ष का रुख

पिछला शुक्रवार कई मायनों में ऐतिहासिक था। पहला, मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार को 2014 में सत्ता में आने के बाद पहली बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरा, वर्ष 2011 के बाद लोकसभा में पहली बार संविधान संशोधन विधेयक गिरा और यह विधेयक अपेक्षित बहुमत के लिए 352 मत नहीं जुटा पाया तथा 54 मतों से गिर गया। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य वर्ष 2029 के चुनावों से पूर्व महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना था। इसका मूल कारण यह था कि इसे परिसीमन विधेयक 2026 से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 2016 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किया जाना है। सरकार ने लोकसभा की सीटों को वर्तमान 543 से 850 करने और राज्यों में विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया, किंतु विपक्षी दलों के सरकार के साथ टकराव और विश्वास के अभाव के चलते यह नहीं हो सका। यह विधेयक उस समय लाया गया जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इससे अविश्वास बढ़ा तथा सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत द्वारा किसी समाधान तक पहुंचने की संभावनाएं कम हो गईं। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विवादों के समाधान की जो परंपरागत विधियां थीं, वे पूर्णतः धराशायी हो गईं। क्षेत्रीय दल हमेशा राष्ट्रीय सुधारों से अधिक अपने गणित को महत्व देते हैं। तथापि सरकार लोकसभा के जनादेश से बच नहीं सकती और उसे भविष्य के लिए सबक लेना होगा। अपने ही विधेयक को पारित कराने में विफल रहने से सरकार की यह सीमा सामने आ गई कि वह अपने बलबूते पर बदलाव नहीं ला सकती। विशेषकर तब जब संस्थागत निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हों। विपक्ष के लिए यह क्षण इस बात का अहसास करता है कि जब वह एकजुट होता है, एक आवाज में बोलता है और साथ रहता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष ने कहा कि यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया और सरकार ने अपने 2023 के रुख को बदल दिया तथा सरकार के इस रुख पर प्रश्न उठाया कि महिला आरक्षण विधेयक वर्तमान में जारी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा जिसमें जाति जनगणना भी हो रही है। इसके साथ ही परिसीमन के संख्यात्मक तंत्र के बारे में भी अविश्वास व्यक्त किया गया और इस आशंका को बल दिया गया कि प्रतिनिधित्व में समानता और संघीय निष्पक्षता के बीच नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है और राज्य एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं किंतु विपक्ष अपनी इस जीत पर लंबे समय तक हर्षोल्लास नहीं मना पाएगा क्योंकि विधेयक पर सरकार को तमगा और राष्ट्रीय नैरेटिव को जोड़ना दो अलग बातें हैं और उसे ऐसी भाषा अपनानी पड़ेगी जिससे वह न केवल भाजपा के जाल से निकले, अपितु जनता को यह भी समझाए कि उसने इस विधेयक का विरोध क्यों किया और वह इस विधेयक के स्थान पर क्या चाहता है क्योंकि उसका राजनीतिक तथा चुनावी भविष्य इस पर निर्भर है। क्षेत्रीय क्षत्रप, विशेषकर तृणमूल की ममता और द्रमुक के स्टालिन इस समय राज्य विधानसभा चुनावों का सामना कर रहे हैं और उन्हें महिला आरक्षण विधेयक के जाल में नहीं फंसना चाहिए।

बंगाल में चुनाव आयोग की 'तार्किक त्रुटियां'

बंगाल में चुनाव नहीं हो रहे, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। विश्वगुरु बनने का सपना तो ट्रम्प ने धराशायी कर दिया, अब कम से कम अपने देश में चक्रवर्ती घोषित होने की तैयारी चल रही है। लेकिन एक विघ्न आन पड़ा है। अश्व केरल और तमिलनाडु के बाजू से कन्नी काट कर निकल गया लेकिन उसे बंगाल में पकड़ लिया गया है। सम्राट की इज्जत बचाकर बंगाल से अश्व छुड़ाने की कोई सूरत नहीं दिख रही। इसलिए अब बंगाल पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। मुकाबला आसान नहीं है। ऊपर से बंगाल का कोई एक तिहाई वोटर किसी भी हालत में भाजपा को वोट नहीं देता। चाणक्य इसी सोच में डूबे थे-अश्वमेध यज्ञ में आन पड़े इस विघ्न का निवारण कैसे हो पुजारी ज्ञानेश कुमार ने यजमान को एक युक्ति सुझाई-क्यों न एक 'विशेष विघ्न निवारण अभियान' चलाया जाए। अंग्रेजी में 'स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूवल' यानी एस.आई.आर.। इस चश्मे से देखें तो आपको बंगाल में एस.आई.आर. के नाम पर हो रहा अजीबो-गरीब घटनाक्रम समझ आने लगेगा। अनेक सवालों के जवाब सूझने लगेंगे। बंगाल में एस.आई.आर. इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है चुनाव आयोग अभूतपूर्व कदम क्यों उठा रहा है यह 'तार्किक त्रुटियों' का खेल क्या है बंगाल में ही अनोखे किस्म की काट-छांट क्यों हो रही है अब आप तथ्य देखिए। बंगाल में एस.आई.आर. शुरू होने के वक्त से ही चुनाव आयोग की जिद थी कि बंगाल को एस.आई.आर. में विशेष सावधानी की जरूरत है, चूंकि वहां की लिस्ट में बड़ी संख्या में अवैध नाम शामिल हैं। लेकिन कभी उसका प्रमाण नहीं दिया गया। दरअसल हर संभव तथ्य चुनाव आयोग के इस शक का खंडन करता था। एस.आई.आर. शुरू होने से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट का आकार एकदम सटीक था। प्रदेश की वयस्क आबादी 7.67 करोड़ थी, जबकि वोटर लिस्ट में 7.66 करोड़ नाम थे, यानी लगभग उतने ही जितने होने चाहिए थे। एस.आई.आर. शुरू होने से पहले नाम जोड़ने की अर्जियां बढ़ी थीं लेकिन बंगाल के चुनावी अधिकारियों ने उनमें से 41 प्रतिशत खारिज कर दी थीं। यानी बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि एस.आई.आर. शुरू होने के बाद बंगाल में बहुत कम नाम कटे। बंगाल में असपैड वोटर, यानी वे वोटर जो पुरानी लिस्ट में किसी रिश्तेदार से नहीं जुड़ सके, 4.5 प्रतिशत थे, यानी छत्तीसगढ़ (3.5) या राजस्थान और मध्य प्रदेश (1.6) से ज्यादा। पहले दौर में बंगाल में कुल मिलाकर 7.7 प्रतिशत नाम कटे, जो फिर राजस्थान (7.6) और मध्य प्रदेश (7.3) के बराबर थे। लब्बोलुआब यह कि बंगाल की वोटर लिस्ट या उसकी शुरुआती छंटनी में कुछ भी अजीब नहीं था। लेकिन चुनाव आयोग ने बंगाल में विघ्न निवारण की ठान रखी थी। इसलिए एस.आई.आर. के पहले चरण के बाद चुनाव आयोग ने भारी नाराजगी जताई और बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए-उत्तर प्रदेश में 4 पर्यवेक्षक लेकिन बंगाल में 30 पर्यवेक्षक। ऊपर से बंगाल में 8,000 माइक्रो पर्यवेक्षक लगाए गए, बाकी देश में एक भी नहीं। जब इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव आयोग ने 'तार्किक त्रुटि' का ब्रह्मास्त्र चलाया। यानी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ने आज के वोटर की अर्जी का 2002 की सूची से मिलान कर उसमें 'तार्किक त्रुटि' ढूंढी। छोटी से छोटी मीन-मेख के आधार पर लोगों को नोटिस दिए गए-नाम की वर्तनी में बदलाव, मां-बाप की आयु में तब और अब कोई विसंगति होने पर, बाप-बेटे की आयु में पचीस अंतर न होने पर आदि। ऐसी तार्किक त्रुटियां बाकी सब राज्यों में भी मिली थीं लेकिन उन्हें रफा-दफा कर दिया गया। इधर बंगाल में चुनाव आयोग ने 60 लाख विवादित मामले ढूंढ निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला देते हुए इन विवादित मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष जज बैठा दिए और उनसे 35 दिन में इनका फैसला करने को कहा। हर जज एक दिन में कम से कम 250 केस निपटा रहा था। जाहिर है

वही हुआ जो होना था। पहले दौर में बंगाल में 58 लाख नाम पहले ही कट चुके थे। शिकायत के आधार पर काटे 6 लाख नाम जोड़ दें तो कुल 64 लाख। ऐसी कटौती बाकी राज्यों में भी हुई लेकिन सब जगह दूसरे दौर में कुछ भरपाई की गई, यानी वोटर लिस्ट के नाम बढ़े। लेकिन बंगाल में अनूठा खेल हुआ-दूसरे दौर में 27 लाख नाम और कट गए। यानी कुल मिलाकर कोई 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से कट गए। 'तार्किक त्रुटि' की लपेट में ऐसे लोगों का नाम भी कट गया, जिनके पास आधार, पैन कार्ड, जन्मप्रमाण और यहां तक कि पासपोर्ट तक है। पता लगा कि दूसरे दौर में जिन लोगों का नाम कटा है, उनमें कोई दो-तिहाई मुसलमान है। नंदीग्राम जैसे क्षेत्र में, जिसमें मुसलमान सिर्फ 25 प्रतिशत है, वहां 95 प्रतिशत मुसलमान का नाम कटा। सुप्रीम कोर्ट इन 27 लाख वोटरों को कहता है कि आप अपील कर लीजिए। अपील की सुनवाई करने वाले ट्रिब्यूनल शुरू भी नहीं हो सके हैं और चुनाव का दिन आ गया है। कोर्ट हमदर्दी दिखाता है, कहता है कोई बात नहीं अगली बार वोट डाल लेना। तो क्या चुनाव आयोग ने बंगाल में विघ्न निवारण कर भाजपा की जीत का रास्ता साफ कर दिया है बेशक चुनाव आयोग ने इस दिशा में भरसक कोशिश की है लेकिन इससे चुनाव का परिणाम तभी पलट सकता है, अगर भाजपा अपने दम पर जीत के नजदीक हो। बंगाल से मिले संकेत इसकी पुष्टि नहीं करते। बंगाल की राजनीति समझने वाले सभी लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग के सहारे के बावजूद भाजपा पीछे चल रही है। तो क्या अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के लिए चुनाव वाले दिन देश भर से जुटाए सुरक्षा बल की मदद ली जाएगी क्या एक व्यक्ति के अहंकार को पूरा करने के लिए देश की बची-खुची लोकतांत्रिक मर्यादा की आहुति दी जाएगी जवाब जल्द ही मिल जाएगा।-योगेन्द्र यादव।

सम्राट की इज्जत बचाकर बंगाल से अश्व छुड़ाने की कोई सूरत नहीं दिख रही। इसलिए अब बंगाल पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। मुकाबला आसान नहीं है। ऊपर से बंगाल का कोई एक तिहाई वोटर किसी भी हालत में भाजपा को वोट नहीं देता। चाणक्य इसी सोच में डूबे थे-अश्वमेध यज्ञ में आन पड़े इस विघ्न का निवारण कैसे हो पुजारी ज्ञानेश कुमार ने यजमान को एक युक्ति सुझाई-क्यों न एक 'विशेष विघ्न निवारण अभियान' चलाया जाए। अंग्रेजी में 'स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूवल' यानी एस.आई.आर.। इस चश्मे से देखें तो आपको बंगाल में एस.आई.आर. के नाम पर हो रहा अजीबो-गरीब घटनाक्रम समझ आने लगेगा। अनेक सवालों के जवाब सूझने लगेंगे। बंगाल में एस.आई.आर. इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है चुनाव आयोग अभूतपूर्व कदम क्यों उठा रहा है यह 'तार्किक त्रुटियों' का खेल क्या है बंगाल में ही अनोखे किस्म की काट-छांट क्यों हो रही है अब आप तथ्य देखिए।

ईरान से सटे समंदर की खामोश नाकेबंदी

एक जहाज नहीं, पूरी सप्लाई लाइन पर किस तरह हो रहा वार?

जाहिद खान

खाड़ी के पानी में हाल ही में जिस ईरानी कारोबारी जहाज को अमेरिकी नाकेबंदी ने ओमान के पानी पर रोका, उसे लेकर सामने आई जानकारी में उसका नाम एमवी टूस्का बताया गया है। कागजों में यह एक सामान्य कंटेनर जहाज है, जैसा रोज दुनिया भर में हजारों चलते हैं, लेकिन इस बार मामला सीधा नहीं था। समुद्री ट्रैकिंग डेटा और विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जहाज चीन के एक औद्योगिक बंदरगाह से निकला, फिर मलेशिया के एक ट्रांजिट पोर्ट पर रुका, जहां कंटेनरों की अदला-बदली हुई और उसके बाद यह ईरान की दिशा में बढ़ रहा था। यह सीधी सप्लाई नहीं थी बल्कि एक ऐसा रास्ता था जिसे जानबूझकर टुकड़ों में बांटा गया था ताकि असली स्रोत और असली गंतव्य को छुपाया जा सके। जहाज की मालिकाना जानकारी भी सीधी और साफ नहीं मिलती, जो अपने आप में इस पूरे मामले की प्रकृति को समझाती है। ऐसे मामलों में अक्सर शैल यानि जाली कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां कागजों पर एक नाम होता है, संचालन किसी और के हाथ में होता है और असली फायदा किसी तीसरे पक्ष तक जाता है। अमेरिका लंबे समय से इसी तरह के नेटवर्क पर नजर रखता आया है क्योंकि उसका मानना है कि ईरान तक पहुंचने वाली कई सप्लाई इसी तरह के घुमावदार रास्तों से गुजरती है। यही वजह है कि इस बार भी कार्रवाई सिर्फ एक जहाज पर नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर केंद्रित नजर आती है जिससे यह जुड़ा हुआ था। अमेरिका ने इस जहाज को ओमान की खाड़ी में रोका और कब्जे में लिया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि इसमें ड्यूल यूज कैटेगरी का सामान था। यह शब्द सुनने में भले तकनीकी लगे लेकिन इसकी अहमियत बहुत गहरी है। ड्यूल यूज का मतलब है ऐसा सामान जो सामान्य उद्योग में भी काम आता है और जरूरत पड़ने पर सैन्य उपयोग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें खास तरह की धातु, मजबूत पाइपिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और औद्योगिक मशीनरी जैसी चीजें शामिल होती हैं। यही वे चीजें हैं जो किसी फैक्ट्री में भी लग सकती हैं और यही वे चीजें हैं जो आगे चलकर मिसाइल या सैन्य ढांचे की रीढ़ बन सकती हैं। इस कार्रवाई को समझने के लिए पीछे जाना जरूरी है क्योंकि यह अचानक लिया गया फैसला नहीं है। वर्ष 2018 में जब अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग किया, उसी समय से पाबंदियों का एक नया और ज्यादा सख्त दौर शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका के वित्त विभाग की एजेंसी ओएफएसी ने कई ईरानी कंपनियों, शिपिंग नेटवर्क और उनसे जुड़े बिचौलियों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू किया। इन पाबंदियों का उद्देश्य सिर्फ हथियारों की सप्लाई रोकना नहीं था बल्कि उन सभी रास्तों को सीमित करना था जिनसे ईरान अपनी तकनीकी और सैन्य क्षमता को मजबूत कर सकता था। यहीं से इस पूरी घटना का असली अर्थ सामने आता है। यह जहाज इसलिए नहीं रोका गया कि उसमें सीधे हथियार मिले थे बल्कि इसलिए रोका गया क्योंकि यह उस सप्लाई लाइन का हिस्सा माना गया जिसे अमेरिका लंबे समय से कमजोर करना चाहता है। जब किसी देश की सप्लाई लाइन को निशाना बनाया जाता है तो असल में उसके भविष्य की ताकत को निशाना बनाया जाता है। यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रहती बल्कि एक बड़े रणनीतिक कदम के रूप में देखी जाती है। ईरान की प्रतिक्रिया को इसी नजरिए से समझना चाहिए। ईरान ने इस कार्रवाई को सीधे समुद्री डकैती कहा और इसका विरोध तीखे शब्दों में किया। यह प्रतिक्रिया सिर्फ भावनात्मक नहीं थी बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी था। ईरान को यह खतरा साफ नजर आ रहा है कि अगर आज एक जहाज रोका गया और उसने कोई मजबूत जवाब नहीं दिया तो कल हर जहाज शक के दायरे में आ सकता है। धीरे-धीरे यह स्थिति ऐसी बन सकती है जहां उसके लिए जरूरी सामान लाना भी मुश्किल हो जाए और यही स्थिति किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इस पूरी घटना की दूसरी परत आर्थिक है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब किसी क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसका असर सिर्फ उस एक जहाज तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समुद्री व्यापार पर पड़ता है। सबसे पहले बीमा कंपनियां उस इलाके को जोखिम वाला घोषित करती हैं जिससे जहाजों का बीमा महंगा हो जाता है। इसके बाद शिपिंग कंपनियां उस रास्ते से बचने की कोशिश करती हैं और अगर जाती भी हैं तो ज्यादा कीमत वसूलती हैं। धीरे-धीरे वही रास्ता जो पहले सामान्य था, महंगा और असुरक्षित हो जाता है। इस तरह बिना किसी खुले एलान के एक तरह की नाकेबंदी शुरू हो जाती है। तीसरी परत इस घटना को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है और वह है इसका अंतरराष्ट्रीय आयाम। यह जहाज चीन से चला था, जिसका मतलब यह है कि यह सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का मामला नहीं है। चीन लंबे समय से ईरान के साथ व्यापारिक और ऊर्जा सहयोग बनाए हुए है और ऐसे कई रास्ते हैं जिनके जरिए यह सहयोग चलता है। अगर इन रास्तों पर इस तरह की रोक लगती है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता बल्कि उन सभी देशों तक जाता है जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों में चीन सीधे टकराव की भाषा भले न अपनाए लेकिन अपनी चिंता जरूर दर्ज कराता है। सबसे अहम बात यह है कि यह पूरी घटना उस बदलती दुनिया की तरफ इशारा करती है जहां जंग अब खुलकर नहीं बल्कि छुपकर लड़ी जा रही है। पहले जंग का मतलब होता था टैंक, मिसाइल और खुला संघर्ष लेकिन अब जंग का मतलब है रास्तों पर नियंत्रण, सप्लाई चेन पर पकड़ और आर्थिक दबाव। जो देश इन तीनों को संभाल लेता है वही असली ताकत बनता है। खाड़ी का इलाका पहले से ही दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता रहा है और यहां होने वाली हर हलचल का असर वैश्विक स्तर पर पड़ता है। अगर आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयां बढ़ती हैं तो इसका असर सीधे आम इंसान की जिंदगी पर भी दिखाई देगा। तेल की कीमत बढ़ेगी, सामान महंगा होगा, सप्लाई में देरी होगी और बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी लेकिन यह सब एकदम से नहीं होगा बल्कि धीरे-धीरे होगा और यही इस तरह की जंग की खासियत है कि यह दिखती कम है और असर ज्यादा करती है।

आखिर में इस पूरी घटना को एक पंक्ति में समझना हो तो यह कहा जा सकता है कि खाड़ी में रोका गया यह जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं था बल्कि एक संकेत था। संकेत इस बात का कि अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि रास्तों पर होगी और जो रास्ता नियंत्रित करेगा वही आने वाले समय की ताकत तय करेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, लाल पैपरवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08863)

पृथ्वी दिवस पर संगोष्ठी, वृक्षारोपण कर हरित भविष्य का लिया संकल्प

कप्तानगंज (कुशीनगर)।

पृथ्वी दिवस के अवसर पर कप्तानगंज स्थित जेपी फार्मेसी कॉलेज के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और हरित पृथ्वी के निर्माण पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद छात्राओं ने माँ सरस्वती को समर्पित वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन दरोगा वीके सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉ. रीना सिंह, ज्ञानवर्धन गोविन्द राव तथा संस्था के संरक्षक श्रीराम प्रसाद उपस्थित रहे। संगोष्ठी के दौरान कॉलेज के शिक्षक डॉ. रोहित कुशवाहा और डॉ. आशीफ अंसारी ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ पृथ्वी के निर्माण पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश और समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसका वन क्षेत्र

होता है, लेकिन वर्तमान समय में जंगलों और वन्य जीवों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों से वृक्षों की कटाई रोकने और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने की अपील की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ज्ञानवर्धन गोविन्द राव ने प्लास्टिक को पृथ्वी का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए कहा कि यह लंबे समय तक मिट्टी में बना रहता है और मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया। वहीं डॉ. रीना सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को अत्यंत आवश्यक बताते हुए सभी से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम के अंत में संस्था के संरक्षक श्रीराम प्रसाद ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. चन्दन कुमार गौड़ ने किया। इस अवसर पर विश्वम्भर प्रसाद, अभिषेक कुमार, रामदरस शर्मा, प्रेमनारायण पांडेय, इरफान अंसारी, सुरेंद्र गौड़, आशुतोष मिश्रा, मेहताब आलम सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

25 हजार का इनामिया गैंगस्टर गिरफ्तार, तमकुहीराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता

कुशीनगर। जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तमकुहीराज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, दिनांक 22 अप्रैल 2026 को थाना तमकुहीराज की टीम ने मु0अ0सं0 41/2024, धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त फरजन पुत्र छोटे निवासी ग्राम चमरौवा, थाना शहजादनगर, जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के बाद उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ मु0अ0सं0 140/2023, धारा 3/5ए/5बी गोवंश निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना तमकुहीराज में मामला दर्ज है। इस गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय के नेतृत्व में उ0नि0 मृत्युंजय सिंह, कांस्टेबल शिवबदन यादव और कांस्टेबल जयनंद यादव की टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।

15 लाख में कैंटीन और 1.14 लाख रूपये में साइकिल स्टैंड की हुई नीलामी

निचलौल। तहसील परिसर स्थित कैंटीन और साइकिल स्टैंड की नीलामी के लिए बोली लगाई गई। इसकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार पीयूष जायसवाल ने की। जहां कैंटीन के लिए सबसे अधिक 15 लाख रूपये की बोली लगाई गई। वही साइकिल स्टैंड के लिए 1.14 लाख रूपये की बोली लगाई गई। बोली लगाने के बाद तहसील प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नायब तहसीलदार पीयूष जायसवाल ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तहसील स्थित कैंटीन और साइकिल स्टैंड की नीलामी के लिए पूर्व में सूचना के आधार पर तहसील सभागार में बोली लगाई गई। इस नीलामी में बोली लगाने के लिए कुल छह बोलीदाता शामिल हुए। कैंटीन की नीलामी के लिए सबसे पहले उमेश ने 180500 की बोली लगाकर शुरुआत की। बोली लगाकर शुरुआत की। उसके बाद बोलीदाता अरुण की ओर से 181000 और राकेश कुशवाहा की ओर से 182000 रूपये की बोली लगाई गई। जबकि बोलीदाता पिंटू यादव और विष्णु प्रजापति ने बोली ही नहीं लगाई। वही बोलीदाता जयगोविंद ने सर्वाधिक 1500000 की बोली लगाकर कैंटीन को अपने नाम कर ली। इसी तरह तहसील परिसर ही स्थित साइकिल स्टैंड की नीलामी में बोलीदाता विशाल पाण्डेय की ओर से सर्वाधिक 140000 की बोली लगाकर अपने नाम कर ली गई। नीलामी प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे नायब तहसीलदार ने आगे कहा कि नीलामी की धनराशि का पचास फीसदी रकम जमा कराने के बाद कैंटीन और। साइकिल स्टैंड को बोलीदाता को सुपुर्द कर दी जाएगी।

निचलौल तहसील परिसर स्थित कैंटीन और स्टैंड की हुई नीलामी, छह बोलीदाताओं ने लगाई बोली

राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता- गोरखपुर मंडल बना चैंपियन, अयोध्या उपविजेता

कुशीनगर।

36वीं राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी वितरण समारोह सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय, अयोध्या में सम्पन्न हुआ। प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 457 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि अयोध्या मंडल 290 अंकों के साथ उपविजेता रहा। मेरठ मंडल ने 250 अंक अर्जित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं वाराणसी मंडल 205 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। ट्रॉफी वितरण समारोह में सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अयोध्या मंडल डॉ. कौस्तुभ कुमार सिंह ने गोरखपुर

मंडल की सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) श्रीमती संगीता सिंह को विजेता ट्रॉफी प्रदान की। इस अवसर पर डायट प्राचार्य रायबरेली श्रीमती दीपिका चतुर्वेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या लालचन्द, नोडल खेल अधिकारी प्रभात चंद्र राय (खंड शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर) सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। कुशीनगर जनपद का प्रतिनिधित्व जिला व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्रा, श्रीमती अनीता सिंह, मदन प्रसाद यादव, शशांक शेखर सिंह सहित अन्य शिक्षकों एवं अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर डॉ. रामजी मौर्य ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि खिलाड़ी भविष्य में भी जनपद का नाम रोशन करते रहें। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी रजनीश द्विवेदी, जयंत भारती, राजेश कुमार, मुकेश नारायण मिश्र, सुरेंद बहादुर सिंह, जया राय, अमितेश कुमार, अमित चौहान, रीता गुप्ता, अशोक कुमार यादव, जिला स्काउट मास्टर नीरज बंका, रविंद्र पांडे सहित अनेक शिक्षकों एवं शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारियों ने गोरखपुर मंडल को प्रदेश चैंपियन बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ।

रील के जुनून में रेलवे ट्रैक पर दौड़ी बाइक, पहुंचा हवालात

जीआरपी की सख्ती- नोनापार हाल्ट से युवक गिरफ्तार, बाइक जब्त

भटनी देवरिया।

रेलवे ट्रैक के बीच मोटरसाइकिल चलाकर सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले एक युवक को जीआरपी थाना भटनी ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से वीडियो में दिखाई दे रही बाइक भी बरामद कर ली गई है। उसके खिलाफ रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रेलवे पुलिस द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों में अपराध नियंत्रण तथा रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस को ट्विटर (एक्स) के माध्यम से एक वीडियो मिला, जिसमें एक युवक नोनापार हाल्ट के होम सिग्नल के पास रेलवे ट्रैक के बीच मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आ रहा था। वीडियो की जांच के बाद युवक की पहचान विकास गौड़ (19 वर्ष) पुत्र मनोज गौड़ निवासी ग्राम उसका, थाना भटनी, जनपद देवरिया के रूप में हुई। बुधवार को जीआरपी भटनी की टीम ने नोनापार हाल्ट स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (संख्या यूपी 53 BY 5683) बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करता है और इसी शौक में उसने रेलवे ट्रैक पर बाइक चलाकर वीडियो बनाया था। वह दोबारा रील बनाने पहुंचा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस संबंध में मु.अ.सं. 192/2026 के तहत धारा 145, 147, 154 रेल अधिनियम में आरपीएफ पोस्ट भटनी में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य, उपनिरीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय, एएसआई कप्तान सिंह, हेड कांस्टेबल अशोक सिंह यादव और कांस्टेबल चन्द्रप्रकाश गुप्ता शामिल रहे।

संचारी रोगों के खिलाफ पीएसपी ने संभाली कमान, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए गांवों में जगाई जा रही अलख

देवरिया। जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रोगी हितकारी मंच (पीएसपी) के सदस्य ग्रामीण इलाकों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक अप्रैल से शुरू हुए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के अंतर्गत पथरदेवा, भटनी और भलुअनी ब्लॉक के गांवों में पीएसपी सदस्यों द्वारा व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को मच्छरों से होने वाली बीमारियों और संक्रमण के खतरों के प्रति सचेत करना है। जिले के इन तीन विकास खंडों के 13 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर गठित यह मंच सीएचओ के नेतृत्व में काम कर रहा है। इसमें ग्राम प्रधान, कोटेदार, शिक्षक, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ फाइलेरिया मरीज भी शामिल हैं। पीएसपी सदस्य गांवों में नालियों की सफाई सुनिश्चित कराने के साथ-साथ एंटी लार्वा दवाओं के छिड़काव पर जोर दे रहे हैं। दस्तक अभियान के तहत घर-घर जाकर लोगों को यह समझाया जा रहा है कि कूलरों में जमा पानी को नियमित बदलें और घर के आसपास जलभराव न होने दें, क्योंकि यही स्थान मच्छरों के पनपने का मुख्य केंद्र बनते हैं। अभियान के दौरान बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, कालाजार और फाइलेरिया जैसे रोगों से बचाव के व्यावहारिक तरीके बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप के साथ मच्छरों और कीड़े-मकोड़ों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए घरों की खिड़कियों में जाली लगवाएं और सोते समय अनिवार्य रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें। इसके अलावा, दूषित जल से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए शुद्ध पेयजल के सेवन और खुले में शौच न करने की अपील की जा रही है। गौरतलब है कि पीएसपी सदस्य न केवल संचारी रोगों, बल्कि टीबी उन्मूलन, आयुष्मान कार्ड बनवाने और फाइलेरिया मरीजों के प्रशिक्षण जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी लगातार सहभागिता कर रहे हैं। वर्तमान अभियान के जरिए भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने जैसी बुनियादी स्वच्छता आदतों को भी जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की मंशा है कि इस जन-भागीदारी के माध्यम से जिले को संचारी रोगों के प्रकोप से मुक्त रखा जा सके।

पथरदेवा, भटनी और भलुअनी ब्लॉक में दस्तक अभियान तेज; फाइलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए घर-घर पहुंच रहे सदस्य

एंटी लार्वा का छिड़काव और स्वच्छता पर जोर, ग्रामीणों को मच्छरदानी के प्रयोग और शुद्ध खानपान की दी जा रही सलाह

मुखर्जी नगर और सोनिया विहार में दबंगों ने रंजिशन कारों में लगाई आग, विरोध करने पर चाकू से जानलेवा हमला

नई दिल्ली। आपसी दुश्मनी में लोगों की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हाल के दिनों ऐसा देखा गया है कि इस तरह की रंजिश में घर के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। राजधानी के मुखर्जीनगर और सोनिया विहार में ऐसे ही दो मामलों में दबंगों ने दो कारों को आग लगा दिया। एक में तो विरोध करने पर चाकू से हमला भी किया गया। मुखर्जी नगर में गली में खड़ी वैगनआर कार को एक व्यक्ति दिनदहाड़े आग लगाकर फरार हो गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में आराम से कार पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कते और आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान और तलाश के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। यह कार ऑनलाइन पुरानी कारों की खरीद-फरोख्त करने वाले व्यवसायी की बताई जा रही है। यह घटना सोमवार की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में टोपी पहने एक युवक कंपी पर बैग लटकाए कार के पास पहुंचता दिखाई दे रहा है। इसके बाद कार के पिछले हिस्से पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा देता है।

मौके पर मौजूद गार्ड को इशारा करने के बाद आरोपी पैदल चला जाता है। कार में लगी आग को देखकर आस-पड़ोस के लोगों ने आग को बुझाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि कार मालिक तरुण कुमार कोहली ने अपनी कार घर के बाहर खड़ी की थी। पुलिस आग लगाने वाले शख्स की पहचान का प्रयास कर रही है। दूसरी घटना में पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में दबंगों ने गली में खड़ी एक कारोबारी की कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कारोबारी की पत्नी व उसके दो बेटों ने जब विरोध किया तो छह लोगों ने गली में महिला को पीट दिया व उसके दो बेटों पर चाकू से कई वार कर दिए।

कारोबारी के घर पर पथराव भी किया। घायल हालत में रीता कश्यप और उनके बेटे अरुण व आर्यन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आर्यन की हालत गंभीर है। अरुण की शिकायत पर सोनिया विहार थाना मामले दर्ज कर लिया गया है। अरुण परिवार के साथ चौथे पुश्ते पर रहते है।

उनके पिता पप्पू का लाजपत राय मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम है। अरुण ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी जितेंद्र अपने घर में बाहरी लोगों को बैठाकर नशा करवाता है और तेज संगीत बजाता है। पीड़ित परिवार विरोध करता था। रविवार रात को कारोबारी ने घर के बाहर कार खड़ी की थी। जितेंद्र के करीबी अमन ने उनकी कार पर देर रात पैट्रोल डालकर आग लगा दी थी। परिवार बाहर गया तो देखा कि कार के पास अमन खड़ा था।

खरगे को नोटिस पर भड़की कांग्रेस- ईसी को बताया गृह मंत्रालय का संलग्न कार्यालयं

नई दिल्ली।

बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की दस्तक के साथ ही देश का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जारी किए गए नोटिस ने इस आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल, पीएम मोदी के खिलाफ खरगे की आतंकवादी वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उनसे जवाब तलब किया है। चुनाव आयोग की इस त्वरित कार्रवाई पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार का संलग्न कार्यालय है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के बजाय केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में काम कर रहा है।

कहा- यह लोकतंत्र पर सीधा प्रहार

उन्होंने कहा कि यह भारतीय संविधान पर एक बड़ा प्रहार है।

जयराम रमेश ने और क्या-क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने लिखा, यह काफी समय से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारों पर नाच रहा है। कई लाख मतों की चोरी को अंजाम देने के बाद, आज उसने गृह मंत्रालय के कार्यालय की तरह काम करने का नया सबूत पेश किया है। उन्होंने आगे लिखा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसका मौजूदा आचरण

संविधान के साथ विश्वासघात है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त पर है। यह पूरा विवाद मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान से शुरू हुआ जो उन्होंने मंगलवार को चेन्नई में दिया था। खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर सरकारी तंत्र और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए विपक्षी दलों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया था। खरगे ने कहा था, ये एआईएडीएमके के लोग अन्नादुरई की फोटो लगाते हैं। वे मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं। वह समानता में विश्वास नहीं रखते। उनकी पार्टी न्याय और समानता में यकीन नहीं रखती।

खरगे की सफाई

हालांकि, इसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके कहने का यह मतलब था कि प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आतंकित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वह लोगों और राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं। मैंने उन्हें शाब्दिक अर्थों में आतंकवादी नहीं कहा। वह विपक्ष को बदनाम करने और दबाने के लिए अपनी शक्ति और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं।

भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने खरगे को 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह नोटिस तमिलनाडु में मतदान और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले जारी किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर युद्धाभ्यास कर रही है. इस एयरशो में सुखोई-30MKI, जगुआर, मिराज-2000 से लेकर तेजस जैसे फाइटर जेट्स और C-295 जैसे टैक्टिकल एयरक्राफ्ट्स ने यहां लैंडिंग की, जिसके वीडियो भी सामने आए है. इंडियन एयरफोर्स पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को आपातकालीन हालात में रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता को आजमा रही है. इसकी को देखते हुए प्रशासन ने एक्सप्रेस-वे का 12 किलोमीटर का हिस्सा सील कर दिया है और ट्रैफिक को एक मई तक के लिए डायवर्ट किया गया है. ऐसी हाईवे एयरस्ट्रिप युद्ध जैसे हालात में सेना के लिए बैकअप रनवे का काम करती है. अगर दुश्मन एयरबेस पर निशाना बनाते है तो वायुसेना इन्हीं एयरस्ट्रिप के जरिए उन्हें जवाब देती है. यहां देश की वायुसेना में शामिल लगभग सभी फाइटर जेट्स ने एक्सरसाइज की है. इस एयरशो से न केवल सेना की तैयारियों को मजबूती मिल रही है, बल्कि सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्रों की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है.

उत्तर भारत में आग बरपाएगा सूरज, दिल्ली-हरियाणा-उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण लू की चेतावनी

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों के लिए लू की चेतावनी जारी की है, जिसमें आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में बताया गया है।

पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों में ऐसी ही स्थिति रहने की आशंका है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक सहित तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों में भी गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वहीं, आईएमडी द्वारा जारी बयान के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के कुछ

हिस्सों में सतें गर्म रहने की संभावना है। दिल्ली के लिए, आईएमडी ने 24 अप्रैल को मुख्य रूप से साफ आसमान और कुछ स्थानों पर लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। नई दिल्ली में बुधवार से शुक्रवार तक लू चलने की आशंका है, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। स्थिति को देखते हुए, आईएमडी ने दिल्ली के लिए दिन भर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लू चलने की आशंका जताई गई है। अधिकतम तापमान 42°C से 44°C के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से काफी अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 22°C से 24°C के बीच रह सकता है। हवाएं हल्की रहने की संभावना है, जो मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से चलेंगी।

जलमार्ग प्रबंधन विभाग ने चेतावनी दी है कि उच्च तापमान से गर्मी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, विशेषकर शिशुओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों जैसे संवेदनशील समूहों में। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे लंबे समय तक धूप में न रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ओआरएस, नींबू पानी और छाछ जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। मौसम एजेंसी ने कृषि संबंधी सलाह भी जारी की है, जिसमें प्रभावित राज्यों के किसानों से आग्रह किया गया है कि वे भीषण गर्मी के बीच फसलों की सुरक्षा और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए शल्की सिंचाई, मल्चिंग और शेड नेट जैसे उपाय अपनाएं। अधिकारियों ने निवासियों से तापमान में लगातार वृद्धि के मद्देनजर सावधानी बरतने का आग्रह किया है, क्योंकि कई क्षेत्रों में लंबे समय तक लू चलने की संभावना है।

होर्मुज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोका- इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में लिया

तेहरान। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपामिनोंडास नाम का यह कंटेनर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। ईरानी नौसेना के मुताबिक जहाज के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। कार्रवाई के दौरान IRGC ने जहाज को रोककर अपने कब्जे में लिया और उसे तट की ओर ले गई। इसके अलावा इजराइल से जुड़े फ्रांसेस्का नाम के दूसरे जहाज को भी कब्जे में लिया गया है। इसके अलावा यूफोरिया नाम के जहाज पर हमला भी किया गया है। इस जहाज पर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले मर्चेंट नेवी में चीफ कैप्टन संजय माहर मौजूद है। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि मेरे शिप पर ईरान की सेना ने फायरिंग की। इसके बाद हम सभी अंदर आ गए। जहाज में मेरे समेत कुल 21 क्रू है। संजय ने शिप के अंदर का एक वीडियो भी भेजा है।

पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर और पीएम शहबाज की अपील पर फैसला

ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका, पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्धविराम (सीजफायर) को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि यह कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे वक्त में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उनसे ईरान पर कुछ समय तक हमले रोकने की अपील की, ताकि ईरान को सही प्रस्ताव तैयार करने का वक्त मिल सके। ट्रम्प ने कहा कि इस अपील को मानते हुए उन्होंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमला रोकने का आदेश दिया है। हालांकि, सेना को पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा गया है। इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी (ब्लॉकेड) जारी रहेगी। उन्होंने साफ किया कि सीजफायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से डील और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले।

बंगाल की पहचान से नहीं होगा खिलवाड़- योगी आदित्यनाथ

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा के प्रचार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोरासांको विधान-सभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोलकाता के मेयर के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें उर्दू के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की पहचान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बंगाल की पहचान काबा से नहीं, बल्कि मां कालीघाड़ी से जुड़ी रही है। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर भी सवाल उठाए। योगी ने कहा कि बंगाल में अव्यवस्था का माहौल वैसा ही है जैसा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में था।

होर्मुज में फिर 3 जहाजों पर बड़ा हमला ! रॉकेट और गोलियों से बनाए निशाना

नई दिल्ली। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज में तीन कंटेनर जहाजों पर हमले की घटनाएं सामने आई है। यह इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों और (UKMTO) के अनुसार, बुधवार को कम से कम तीन जहाजों पर गोलीबारी की गई। इन हमलों में रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड और गोलियों का इस्तेमाल हुआ। पहला हमला ओमान के उत्तर-पूर्व में हुआ, जहां लाइबेरिया झंडे वाले एक कंटेनर जहाज के ब्रिज (जहाज का कंट्रोल रूम) को नुकसान पहुंचा। जहाज के कप्तान ने बताया कि एक गनबोट तेजी से उनकी ओर बढ़ी और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई आग या पर्यावरणीय नुकसान नहीं हुआ और सभी चालक सदस्य सुरक्षित हैं।दूसरी घटना में एक पनामा-झंडे वाला जहाज ईरान के पश्चिम में करीब 8 नॉटिकल मील दूरी पर फायरिंग का शिकार बना। हालांकि इस जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ और इसका पूरा स्टाफ सुरक्षित रहा। तीसरी घटना में एक और लाइबेरिया-झंडे वाले जहाज पर उस समय गोलीबारी हुई जब वह स्ट्रेट से बाहर निकल रहा था। इस जहाज ने सुरक्षा के लिए बीच समुद्र में रुकने का फैसला किया। इसमें भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और क्रू सुरक्षित रहा। रिपोर्ट के अनुसार, एक जहाज ने (UKMTO) को सूचना दी थी कि एक संदिग्ध गनबोट उसकी ओर बढ़ रही है। इसके कुछ ही समय बाद हमला हुआ।

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को खतरे में डाला, मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली।

I-PAC पर ईडी की रेड मामले में सीएम ममता बनर्जी के दखल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को ही खतरे में डाल दिया है. कोर्ट ने आगे कहा कि ये कोई केंद्र और राज्य का झगड़ा नहीं है. हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा. मामले की सुनवाई के दौरान जब ममता बनर्जी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने राज्य और केंद्र के बीच के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट के सामने मौलिक अधिकार लागू करने की अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है, तो जस्टिस मिश्रा ने इसपर अपनी टिप्पणी की. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राय के बीच का मामला नहीं है.यहां राय का कौन

सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का सीएम है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.आप इसे राज्य और केंद्र सरकार के बीच का झगड़ा नहीं कह सकते. एसजी मेहता (ईडी के लिए) दोष साबित करने वाले सबूत छीन लिए गए। जस्टिस मिश्रा पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया गया था.

हमने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में ऐसा दिन आएगा जब कोई मौजूदा सीएम ऐसी जगह पर घुस जाएगा जहां एक जांच एजेंसी जांच कर रही हो.आप कहते हैं कि यह राय और केंद्र के बीच का झगड़ा है ? पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि हम अभी भी सुनवाई योग्य होने पर हैं . ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. एसजी दिखावा कर रहे हैं।

जब हम फैक्ट्स पर आएंगे तो हम निश्चित रूप से अदालत को मना लेंगे. इस दिखावे की कोर्टरूम में कोई जगह नहीं है.

एमपी-एमएलए अदालत में धारा 311 पर बहस हुई पूरी, 2 मई को आएगा फैसला

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 से संबंधित आवेदन पर बहस हुई। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखते हुए दो मई को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय द्वारा दायर धारा 311 के आवेदन पर अदालत में बहस हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय के लिए अगली तारीख दो मई तय की। पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी। इससे पूर्व 28 मार्च की सुनवाई में वादी पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने और उसकी फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की थी। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 311 सहपठित धारा 91 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आवाज के नमूने का मिलान पहले से दाखिल सीडी से, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फॉरेन्सिक लैब) में कराने का अनुरोध किया गया था। इस मांग का राहुल गांधी के अधिवक्ताओं ने विरोध किया था। यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा अक्टूबर 2018 में दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था,

जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत प्रदान की थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। अदालत ने उनके बयान के बाद वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत गवाह पेश किए जाते रहे हैं। इससे पहले 20 फरवरी को भी राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें अदालत ने उनसे आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि, उनके अधिवक्ता द्वारा कोई अतिरिक्त साक्ष्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

मिर्जापुर में भीषण हादसा- ट्रक समेत चार वाहन आपस में टकराए, बोलेरो में लगी आग, दुर्घटना में 11 लोगों की मौत

डूमंडगंज। रीवा-मिर्जापुर हाईवे पर स्थित डूमंडगंज घाटी में बुधवार की रात आठ बजे ट्रक, कार, बोलेरो और ट्रेलर आपस में टकरा गए। इसके बाद बोलेरो में आग लग गई। बोलेरो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत की खबर है। सूचना पर मौके पर सीओ अन्य अधिकारी पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार हादसे में बोलेरो सवार दो महिला, दो बच्चे और पांच पुरुषों की मौत हो गई है जबकि स्वीफ्ट कार सवार और ट्रक चालक की भी दुर्घटना में जान चली गई। स्विफ्ट कार चालक मृतक की पहचान जय प्रकाश (26) पुत्र मुन्नर निवासी परसिया दुबे रावर्ट्सगंज सोनभद्र के रूप में हुई है। डूमंडगंज घाटी में रात को आठ बजे गिट्टी लगा ट्रेलर उतर रहा था। उसके पीछे स्विफ्ट कार सवार आ रहे थे। कार के पीछे दाल लगा ट्रक आ रहा था। दाल लदे ट्रक के पीछे बोलेरो सवार चल रहे थे। दाल लगे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। उसने आगे स्विफ्ट कार में टक्कर मारी। स्विफ्ट कार आगे ट्रेलर में टकरा गई। टक्कर में पीछे से आ

रही बोलेरो ट्रक में टकराई। आपस में गाड़ियों के टकराने के चलते बोलेरो में आग लग गई। आग लगने से बोलेरो सवार सभी लोग गाड़ी में फंस गए। बोलेरो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने डूमंडगंज पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर डूमंडगंज, हालिया व अन्य थाने की फोर्स फायर ब्रिगेड टीम के साथ मौके पर पहुंची। सीओ लालगंज अमर बहादुर भी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां बोलेरो की आग को बुझाने में लगी रहीं। घंटों मशक्कत की बात बोलेरो की आग पर काबू पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि बोलेरो सवा नौ लोगों की मौत हुई है। पुलिस शवों को बोलेरो से निकालकर शिनाख्त में जुटी है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि घाटी में ट्रक उतार रहा था। उसके पीछे कार थी। कार के पीछे एक ट्रेलर था। उसके पीछे बोलेरो थी।

आपस में सभी गाड़ियां टकरा गईं। बोलेरो में आग लग गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने के लिए लगी है। बोलेरो सवार लोग जले हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है।